

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—150/2018/223 (2018/00150)

1. रामनिवास पुत्र लादू माली,
2. फूलचंद पुत्र काना माली,
3. विश्राम पुत्र सुवालाल माली,
4. मुकेश पुत्र सुवालाल माली,
5. मंगलचंद पुत्र रामदयाल माली,
6. प्रभूलाल पुत्र रामदयाल माली,
7. तेजमल पुत्र रामदयाल, जाति माली,
8. गणेश पुत्र रतनलाल, जाति माली,
9. बोदूलाल पुत्र रतनलाल जाति माली,
10. सुखराम उर्फ पप्पू पुत्र सुवालाल माली,
समस्त जाति माली, निवास मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, तहसील
किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बिरदीचंद पुत्र रामलाल, जाति माली,
2. शंकरलाल पुत्र रामलाल, जाति माली,
3. जगदीश पुत्र रामलाल, जाति माली,
4. बुद्धकरण पुत्र रामलाल, जाति माली,
समस्त निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, तह० किशनगढ़, जिला
अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

5. राजू पुत्र गोपाल माली, नि० मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध
निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 24.4.2018
अंतर्गत वाद संख्या 49/2005.

उपस्थित:—

1. श्री इंद्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो० संख्या 3 व 4.
3. रेस्पो० संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:— 27.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो० संख्या 1 से 4 ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज०काश्त०अधि० 1955

के तहत पेश कर निवेदन किया कि पटवार क्षेत्र किशनगढ़, तहसील व जिला अजमेर के खसरा संख्या 2333 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि के उत्तर-पूर्व हिस्से में वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक, हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 29.6.2005 को जबरन उपरोक्त भूमि में से रास्ता निकालने के लिये आमादा हो गए। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे। विद्वान अधी०न्याया० ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2018 को वादीगण/रेस्पों संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये। अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 उपस्थित। अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। खसरा संख्या 2333 के वादीगण के अतिरिक्त छीतर, श्रीकिशन पुत्र नौरत 1/2 हिस्से के सह खातेदार, काबिज काश्तकार है। खसरा संख्या 2333 के उत्तर दिशा में सीव से 25 फीट चौड़ा रास्ता जो पूर्व तक जाकर आगे दक्षिण दिशा में घुमाव खाकर जाता है, अवस्थित है। यह रास्ता 5 दशक पुराना होकर ग्रामवासियों के उपयोग उपभोग में आ रहा है। उक्त खसरा नंबर 2333 के दक्षिणी सीमा पर विधायक कोष से हैण्डपंप तथा गांवाई जनसहयोग से श्री श्री 108 श्री गिरधारी दास महाराज का आश्रम बना हुआ है जिसमें वादीगण ने भी सहयोग किया है। उक्त आश्रम का मुख्य एवं एकमात्र दरवाजा खसरा संख्या 2333 में उल्लेखित रास्ते पर पश्चिम दिशा में देखता हुआ है। अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासी उक्त रास्ते में आवागमन करते हैं। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निस्तारण की संख्या अधिकतम दर्शाने के दृष्टिकोण से वास्तविक तथ्यों से परे जाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ था बल्कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.4.2018 को उपस्थित होकर आगामी तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया था। दिनांक 24.4.2018 को कैम्प में न तो निर्णय लिखा गया था, न ही मजमें आम में निर्णय सुनाया गया था। यदि कोई भी निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में लिखा जाता है तो सामान्यतः अंतिम पृष्ठ पर पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये जाते हैं। अधी०न्याया० द्वारा 6 पृष्ठों का निर्णय लिखाया गया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रशासनिक कार्यवाहियां की गई थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 24.4.2018 को 6 पृष्ठ का निर्णय का डिक्टेसन दिया जाना संभव नहीं था। बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० द्वारा मृत व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 हरजी पुत्र लादू के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अधी०न्याया० को मजमें आम में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी हो चुकी थी। अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के खिलाफ होने से भी निरस्तनीय है। अधी०न्याया० ने वादी की साक्ष्य भी नहीं ली थी इसके बावजूद बिना वादी की साक्ष्य लिये वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी०न्याया० ने किसी भी साक्ष्य को प्रदर्श भी नहीं किया है। अधी०न्याया० के समक्ष वादी द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वाद खारिज योग्य था। बहस में आगे कथन किया

- कि अधी०न्याया० ने राज०काश्त०अधि० की धारा 211 के प्रावधानों को भी दृष्टिगत नहीं किया है । योग्य अधी०न्याया० के समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रमाण था कि वाद अधीन भूमि खसरा नंबर 2333 के प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 के अतिरिक्त अन्य भी 1/2 हिस्से के सहखातेदार काबिज काश्तकार है जिन्हें वादी ने वाद में पक्षकार कायम नहीं किया जिससे भी वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी०न्याया० ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 3 का अवधारण करने में त्रुटि कारित की है । वाद विधिक रूप से संस्थित नहीं किया गया था तो उसके रहते हुए वांछित अनुतोष के अधीन प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं था । विशेषतः ऐसी स्थिति में जब सिविल न्यायालय में लंबित वाद में दिनांक 9.8.2007 को न्यायालय कमिश्नर द्वारा मौके पर खसरा संख्या 2333 के उत्तर दिशा में रास्ता होने एवं उक्त रास्ता पूर्व दिशा से घुमाव खाकर दक्षिण दिशा में जाना प्रमाणित था जो आज भी मौके पर प्रचलित है । अधी०न्याया० ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2009 (1) पेज 139, सुप्रीमकोर्ट 1969 पेज 255 एवं डी०एन०जे० 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।
5. विद्वान वकील रेस्पोजेंट संख्या 3 व 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । अधी०न्याया० द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की है । विवादित आराजी खसरा नंबर 2333 रकबा 18-4-00 बीघा आराजी रेस्पोजेंट की सहखातेदारी की आराजी है जिसके उत्तर-पूर्वी हिस्से पर आपसी समझौते अनुसार रेस्पोजेंट काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि में अपीलांटस के कोई हक, अधिकार एवं स्वत्व निहित नहीं है न ही विवादित आराजियात से कोई संबंध व सरोकार है । अपीलांटस जबरन विवादित आराजियात से रास्ता निकालने पर आमादा है । सिलोरा से किशनगढ़ खसरा नंबर 2338, 2336, 2337 जो मुख्य रास्ता गमन करता है उक्त रास्ते से किशनगढ़ शहर में रास्ता जाता है जिसके खसरा नंबर 2358, 2448, 2451 से होता हुआ पुनः सिलोरा-किशनगढ़ मुख्य मार्ग के खसरा नंबर 2338 में निहित हो जाता है । उक्त रास्ते के खसरा नंबर 2451 व 2448 से लगते हुए वर्तमान अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात है । उक्त मार्ग से ही अपीलांटस एवं इनके पूर्वज सदियों से आते जाते रहे हैं अन्य कोई सार्वजनिक मार्ग स्थित नहीं है । आज दिनांक तक रेस्पोजेंट की सहखातेदारी की भूमि में से होकर कभी भी कोई रास्ता रिकार्ड अथवा मौके पर नहीं है । रेस्पोजेंट द्वारा उक्त आराजियात में अपने पक्के मकान बना रखे हैं एवं अपने अराध्य देव का निजी आश्रम बना रखा है जिससे अपने घर से आश्रम तक एवं आपसी समझौते से बटे हुए खेतों पर जाने के लिये निजी रास्ते बना रखे हैं जो सार्वजनिक नहीं हैं । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा रास्ते बाबत् प्रकरण सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज दिनांक कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है । सिविल न्यायालय के प्रकरण का हवाला देकर यह कथन करना कि सिविल न्याया० में वाद विचाराधीन है जिससे अपीलांटस को पाबंद नहीं किया गया जा सकता है किया गया कथन गलत है । प्रतिवादी की मृत्यु बाबत् स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष कोई सूचना नहीं दी गई एवं मृतक प्रतिवादी की ओर से लगातार पैरवी की जाती रही है जिससे अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय शून्य की परिभाषा में नहीं आता है । अधी०न्याया० का निर्णय व

डिक्री विधिसम्मत है । जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि अधी०न्याया० द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया गया तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) ने अधी०न्याया० के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया है । [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने के उपरांत अधी०न्याया० ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की है । अधी०न्याया० द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु अपीलांटस द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर दो बार अंतिम अवसर प्रदान किये गये इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि अधी०न्याया० द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी०न्याया० ने प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण करते हुए लोक अदालीत में मजमें आम में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी०न्याया० द्वारा लोक अदालत में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है । अधी०न्याया० के निर्णय पर अपीलांटस के हस्ताक्षर भी है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलांटस को सुना नहीं गया हो । केवल वादी साक्ष्य नहीं लिये जाने के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि [वादीगण/रेस्पो०](#) द्वारा वादपत्र में समस्त तथ्यों का अंकन कर रखा है । पत्रावली के अवलोकन से विवादित आराजियात में अपीलांटस का कोई लोकस नहीं पाया जाता है । विद्वान अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निर्णय पारित करते हुए [वादीगण/रेस्पो०](#) का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है । अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं ।
7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर